महामहिम श्री प्रदीप कुमार ग्यावली द्वारा संबोधन नेपाल के विदेश मंत्री

नई दिल्ली, 15 जनवरी 2021

राजदूत डॉ टीसीए राघवन, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए उपस्थित राजनयिक, विद्वान और प्रोफेसर और वर्चुअल शामिल लोग,

मीडिया के मित्र,

देवियों और सज्जनों

इन प्रतिष्ठित दर्शकों के समक्ष बोलना मेरे लिए वास्तव में बहुत खुशी की बात है।

मैं इस अवसर के लिए और भव्य से स्वागत के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। राजदूत डॉ. राघवन को मेरा परिचय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अनेक प्रख्यात लोगों का इस चर्चा में वर्चुअल रूप से जुड़ना आप सभी को नेपाल में रूचि दर्शाती है।

मेरे लिए, यह नेपाल के बारे में आपकी सद्भावना के साथ-साथ नेपाल-भारत संबंधों से जुड़े महत्व को दर्शाता है।

प्रिय मित्रो

नेपाल आपके लिए अपरिचित नहीं है। न ही नेपाल में हाल के दशकों में जिस तरह का राजनीतिक बदलाव हासिल किया है।

विश्व में संभवत: ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक समाज सशस्त्र संघर्ष से शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में सुचारू रूप से बदलाव करने में सफल हो, सामाजिक-राजनीतिक पुनर्गठन के एजेंडे पर सहमत हो, गोली से मतपत्र तक की यात्रा पूरी करे और पूरी प्रक्रिया का समापन लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा समावेशी संविधान बनाने में होता है।

हम जो संविधान बनाते हैं वह किसी भी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह हमारे समाज में पिछड़े समुदायों के साथ सामाजिक-आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। पिछले तीन साल में हमारा ध्यान इसी संवैधानिक आकांक्षा को वास्तविकता में बदलने पर रहा है।

हमारे जैसे विविध समाज में, जहां राजनीतिक ताकतों की प्रतिद्वंदी विचारधारा होती हैं, वहां संक्रमण का प्रबंधन आसान नहीं था। लेकिन, हमने इसे दृढ़ संकल्प के साथ किया। समाज को रूपांतरित और सबको सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया।

मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक परिवर्तन को पूरा करने में हमें पड़ोस और विश्व भर में अपने सभी मित्रों और शुभचिंतकों से बहुमूल्य समर्थन मिला, जिसके लिए हम सबसे आभारी हैं।

संविधान के बाद का संक्रमण कम रहा। जैसाकि संविधान में परिकल्पित है, 2017 में स्थानीय, प्रांतीय और संघीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराए गए थे। 20 वर्ष के अंतराल के बाद स्थानीय निकायों को निर्वाचित नेतृत्व मिला और हमने जमीनी स्तर पर सशक्त स्थानीय निकायों के सकारात्मक प्रभावों को पहले ही देखना शुरू कर दिया है। नव-स्थापित प्रांतीय सरकारों ने भी अपने महत्व को साबित किया है।

हाल ही में नए सिरे से जनादेश के लिए संप्रभु लोगों के पास जाने का फैसला लिया गया है। ये चुनाव लोकप्रिय इच्छा व्यक्त करने और हमारी लोकतांत्रिक बुनियाद को और सुदृढ़ करने के लिए एक और महत्वपूर्ण अवसर होंगे।

राजनीतिक प्रक्रिया ने एक तय रास्ता अपनाया, हमारा ध्यान अब लोगों की स्वतंत्रता के अन्य पहलुओं पर है, नामत: गरीबी और अल्पविकास से स्वतंत्रता; वंचित जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति; बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में चिंता से स्वतंत्रता; एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता।

हम पूर्णतया जानते हैं कि राजनीतिक लाभ तभी कायम रह सकता है जब हम एक मजबूत आर्थिक बुनियाद तैयार कर सकें।

और इस उद्देश्य के लिए, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व में हमारी सरकार 'समृद्ध नेपाल, खुशहाल नेपाली' की राष्ट्रीय आकांक्षा को साकार करने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए हमने अपनी आर्थिक विकास प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित किया है, समयबद्ध लक्ष्यों को परिभाषित किया है और उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ लागू किया है।

विगत तीन वर्षों में नेपाल ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के विभिन्न आयामों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। परिवर्तन की गति और तीव्रता कभी अधिक दृश्यमान और प्रभावशाली नहीं रही है। देश ने अधिकांश विकास संकेतकों पर प्रगति की है।

कोविद 19 महामारी से पूर्व नेपाल उच्च आर्थिक विकास वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में था। विगत 3 वर्षों से विकास दर लगातार 6.5% से ऊपर थी। साथ ही गरीबी के स्तर में हर वर्ष डेढ़ प्रतिशत की कमी की गई।

इसी अवधि के दौरान, नेपाल ने 14 से अधिक वैश्विक संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किए। यह उत्साहजनक है कि हम मानव विकास सूचकांक में सुधार करने, व्यापार करने में सुगमता, भूख सूचकांक, शांति सूचकांक, कानून का शासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और पारदर्शिता, खुशहाली सूचकांक, और लैंगिक समानता में शीर्ष 10 देशों में शामिल थे।

व्यापार घाटे में 10% की कमी आई है; एफडीआई बढ़ा है; विकास सहयोग बढ़ा है; और हम विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में बेहतर स्थिति में हैं।

सीमा पार रेलवे, पूर्व-पश्चिम इलेक्ट्रिक रेलवे, जलमार्ग, नए हवाई अड्डों, काठमांडू-तराई एक्सप्रेसवे सहित नेपाल के विकास के लिए महत्वपूर्ण सामरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्य आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के विस्तार के साथ-साथ मध्य पर्वतीय राजमार्ग का निर्माण और उन्नयन चल रहा है।

सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के आदर्श वाक्य से निर्देशित, सरकार ने योगदान आधारित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। स्वास्थ्य बीमा साठ से अधिक जिलों में पहुंच चुका है।

कोविद 19 के बावजूद, स्कूल नामांकन 98% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी विगत माह ही हमने 396 शहरी और ग्राम नगर पालिकाओं में एक साथ बनाए जाने वाले 5 से 15 बिस्तरों की क्षमता के नए अस्पतालों का शिलान्यास किया था। यह देश के दूरस्थ भाग में भी स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई एक ऐतिहासिक घोषणा थी।

भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण कार्य पूरे होने वाले हैं जिनमें बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर की क्षतिपूर्ति भी शामिल है। सात लाख निजी घर बनाए गए हैं और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इनमें भारत सरकार की उदार सहायता के अंतर्गत निर्मित 47 हजार घर शामिल हैं। संवेदनशील स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बस्तियों में शिफ्ट कर दिया गया है।

हमें इस बात का ध्यान है कि ये उपलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं। अभी बहुत कुछ करना है।

हमारी विकास की आवश्यकताएं अपार हैं और आकांक्षाएं असीम हैं। संसाधन सीमित हैं और चुनौतियां असीम हैं और इनमें से कई चुनौतियों का हम अकेले सामना नहीं कर सकते; हमारी कई आकांक्षाएं हम अपने अकेले प्रयासों से पूरी नहीं कर सकते।

यही कारण है कि हमें भागीदारों की आवश्यकता है; हमें मित्रों की आवश्यकता है। इस तरह की मित्रता की प्राकृतिक शुरुआत पड़ोस है। हम अपने बड़े पड़ोसियों की समृद्धि के साथ समृद्धि की हमारी आकांक्षा के बीच एक प्राकृतिक संबंध देखते हैं।

यह हमारे लिए एक सुदृढ़ आर्थिक साझेदारी है जो हमें विकसित करने के लिए और हमारी क्षमता दिलाने के लिए सक्षम बनाती है;

- एक साझेदारी जो नेपाल की संरचनात्मक बाधाओं को लैंडलॉक और अल्प विकसित देश के रूप में दूर करने में मदद करती है;

- एक साझेदारी जो पारस्परिक रूप से पुरस्कृत और लाभकारी व्यापार संबंधों को बढ़ावा देती है;

- एक साझेदारी जो दुस्त्रियीकरण, निवेश के प्रवाह, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की प्रक्रिया को

प्रेरित करती है और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को मूल्य श्रृंखला में जोड़ती है;

- एक साझेदारी जो निरंतर आर्थिक विकास और विकास के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उत्थान की ओर ले जाती है; और
- एक साझेदारी जो हमारे संबंधों को हमारे लोगों के जीवन के लिए प्रभावशाली बनाती है।

प्रतिष्ठित मित्रों,

हमारे दोनों देश भूगोल के साथ-साथ इतिहास, प्रकृति के साथ-साथ संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। हमारे दोनों समाज प्राचीन ज्ञान और विरासत से धन्य हैं जिनकी कालातीतता को सार्वभौमिक रूप से पहचाना गया है।

जब हम आज अपने संबंधों के संदर्भ को देखते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम लोगों की आकांक्षाओं की कितनी सेवा कर सकते हैं; हम विकास और विकास की खोज के लिए एक-दूसरे का किस हद तक समर्थन कर सकते हैं।

हमारे दोनों देश अत्यधिक विविध समाज हैं और इस विविधता के प्रबंधन के हमारे अपने अनूठे अनुभव हैं। हमारी समान आकांक्षाएं हैं और संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों की खोज में समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारी विकासात्मक चुनौतियां भी समान हैं। हमारे देशों में गरीबी अभी भी महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करने की तात्कालिकता का सामना करते हैं कि हमारे लोगों के पास एक सभ्य घर, सभ्य कपड़े और गुणवत्तापूर्ण भोजन हो; कि हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है जो उन्हें सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाती है।

ये आम तात्कालिकता हमें बताती हैं कि हमारी समकालीन चर्चा में आर्थिक विकास अधिक महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए; हमें इस उद्देश्य के लिए घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी बनाने की आवश्यकता क्यों है; और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक संबंध महत्वपूर्ण क्यों हैं।

नेपाल-भारत संबंध राजनीतिक और आर्थिक चर्चा के साथ-साथ लोगों के बीच के स्तर पर अद्वितीय संबंधों का विशाल संगम हैं। इसे केवल एक आयाम तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

राजनीतिक क्षेत्र में दोनों देशों को लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रथाओं और शासन प्रणाली के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता से समीप लाया गया है। भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि कैसे लोकतंत्र और विकास को एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि लोगों की समग्र प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।

नेपाल लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है ताकि हमारे लंबे संघर्षों का लाभ अटूट रहे।

अपने बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हमने सहयोग के लगभग सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय तंत्रों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। लगभग तीन दर्जन तंत्र हैं जो वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

मैं इस बार अपने विशिष्ट समकक्ष, भारत के विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के साथ ऐसे ही एक महत्वपूर्ण तंत्र की बैठक करने के लिए दिल्ली आया हूं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पड़ोसियों के बीच संबंधों की अपनी विशेषताएं हैं। आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की संवेदनाओं और चिंताओं के लिए समान इस तरह के रिश्ते की नींव को मजबूत करने में योगदान करते हैं। संबंधों के दीर्घकालिक और सद्भाव के लिए विश्वास का निर्माण और पोषण नितांत आवश्यक है।

इस भावना के साथ, हम शेष क्षेत्रों में सीमा संरेखण के प्रश्न को हल करने की दृष्टि से बातचीत शुरू करना चाहते हैं। आपमें से कई लोग इस बात से अवगत हो सकते हैं कि नेपाल और भारत 1,800 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा हैं जिनमें से अधिकांश संयुक्त रूप से मैप किए गए हैं। केवल कुछ किलोमीटर के हिस्सों में ही काम पूरा होना बाकी है।

इन खंडों में एक सहमत सीमा संरेखण ढूंढना न केवल हमें पूरी तरह से तय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चरण में ले जा सकता है, लेकिन यह भी सकारात्मक आकर्षण पैदा करने में मदद कर सकते हैं और द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास और अत्यधिक विश्वास पैदा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हम काम कर सकते हैं और उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं।

हालांकि, दोनों पक्ष चर्चा के जरिए सीमा प्रश्न को हल करने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन हमने यह भी बुद्धिमत्ता दिखाई है कि एक क्षेत्र में अंतर के बावजूद हमारे समग्र संबंधों की गति जारी है। हम यह भी ध्यान रखें कि हमें हमारे बीच किसी भी बकाया मुद्दे को हमेशा के लिए नहीं रहने देना चाहिए जो अन्यथा मैत्रीपूर्ण संबंधों में अड़चन बने।

देवियो और सज्जनो

नेपाल के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। हालांकि, द्विपक्षीय व्यापार घाटे की समस्या बड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था इस चिंताजनक उच्च व्यापार असंतुलन को बनाए नहीं रख सकती ।

द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था की समीक्षा की प्रक्रिया में हमने कुछ ऐसे उपायों का प्रस्ताव किया है जो हमें कुछ वास्तविक स्थान प्रदान करेंगे और हमें अपने निर्यात आधार का विस्तार करने में मदद करेंगे। हम इन उपायों पर सकारात्मक और आगामी विचार की आशा करते हैं। नेपाल व्यापार में भारत का प्रतिस्पर्धी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपमें से कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब मैं यह कहूंगा कि नेपाल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भारत के हित में भी है।

हमने इसी तरह वर्तमान पारगमन व्यवस्थाओं के विस्तार और सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ

प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। हम इस समीक्षा प्रक्रिया का एक प्रारंभिक निष्कर्ष भी देखना पसंद करते हैं।

नेपाल और भारत प्राकृतिक और मानवीय दोनों संसाधनों से संपन्न हैं। 21वीं सदी केवल ऐसी क्षमता और संसाधनों की सदी नहीं होनी चाहिए जो अनुपयोगित हो और अप्रयुक्त हो। यह सपने साकार करने की सदी होनी चाहिए।

संभावनाओं की बात करें तो पनबिजली विकास द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इससे हमारे दोनों देशों के लोगों और उद्योगों को फायदा होगा। हमें अतीत में सहमत परियोजनाओं को ईमानदारी से लागू करके एक सफलता की गाथा बनाने की आवश्यकता है। पंचेश्वर परियोजना सर्वोपरि आती है। इस परिवर्तनकारी मेगा परियोजना पर हमारी हालिया चर्चा उत्साहजनक रही है। एक बार चालू होने के बाद पंचेश्वर न केवल अपने दम पर एक बड़ी परियोजना होगी बल्कि इस बात की सफलता की गाथा भी तय करेगी कि हम अपने विशाल जल संसाधनों के दोहन में लागत और लाभ के बंटवारे की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं।

भारतीय निवेशकों को पहले से ही नेपाल में हाइड्रो परियोजनाओं पर निवेश करने में कर्षण हो रहा है। बड़े पैमाने पर दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं-एक सार्वजनिक उद्यम द्वारा और दूसरी एक निजी निवेशक द्वारा।

इस प्रकार की परियोजनाओं से बिजली के सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए, दोनों देशों ने बिजली के मुक्त व्यापार के बारे में प्रावधान को शामिल करते हुए 2014 में एक द्विपक्षीय बिजली व्यापार समझौता किया। बिजली व्यापारी और डेवलपर्स सीमा पार बिजली व्यापार के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया जारी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नेपाल की मंशा कम से कम बीबीआईएन देशों के बीच बिजली के निर्बाध व्यापार की जल्दी संभावना देखने की है।

संयोजकता के महत्व पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता । हमें वायु-सेवा संयोजकता, हवाई मार्गों और सड़क और रेल संबद्धता को और विस्तार देने की आवश्यकता है। इनमें रेलवे, जलमार्ग और सीमा पार पारगमन, परिवहन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अन्य घटक शामिल हैं।

हाल ही में, हमने अपनी कुछ प्रमुख संयोजकता परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे प्रधानमंत्रियों ने एक वर्ष पहले मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया था, जो इस क्षेत्र में पहली सीमा पार पाइपलाइन है। हम पाइपलाइन अवसंरचना अधिक विस्तार की बात कर रहे हैं।

माल की सीमा-पार आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए दो प्रमुख सीमा बिंदुओं पर एकीकृत चेक-पोस्ट स्थापित और चालू की गई हैं। इस प्रकार के और भी चेक-पोस्ट बनाए जाएगें।

सीमा-पार रेलवे पर भी प्रगति हुई है। काठमांडू रक्सौल रेलवे के विकास के लिए अपेक्षित प्रारंभिक

कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे विशेषज्ञों ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर भी कार्रवाई की है। इन पहलों से न केवल हम और अधिक जुड़े रहेंगे बल्कि भूमि से लेकर भूमि से जुड़ी स्थिति तक नेपाल के परिवर्तन में भी योगदान मिलेगा।

संबंधित सीमा से परे, हमारे दोनों देश क्षेत्रीय समृद्धि और बेहतर क्षेत्रीय सहयोग का सपना साझा करते हैं। हम सार्क, बिम्सटेक और बीबीआईएन में मिलकर काम करते हैं। यहां तक कि कोविड 19 महामारी के दौरान भी हमने सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएं तलाशी थीं। हम सार्क नेताओं के वर्चुअल समिट को बुलाने की पहल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, नेपाल और भारत दोनों विकासशील देशों के सामने विशिष्ट रूप से सामना करने वाले मुद्दों की पैरवी करते हैं और एक न्यायकर्ता और अधिक समावेशी वैश्विक विकास के लिए आवाज उठाते हैं। हम सभी देशों के लिए बेहतर समान अवसर के लिए बोलते हैं।

प्रिय मित्रो,

हम घर और विदेश दोनों में परिवर्तित स्वरूप में हैं। तदनुसार, हम बाहरी विश्व के साथ अपने संबंधों में नए दृष्टिकोण कार्यान्वित करना चाहते हैं।

हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता हमारी सीमाओं पर शुरू होती है। भारत के बारे में बात करते हुए, हमारी मंशा हमारे संबंधों की नींव को मजबूत करना है; इसका विस्तार और समेकन करने के लिए; और संबंधों को अगले स्तर पर लाने के लिए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट और सुस्पष्ट है।

हम विभिन्न आकार, आबादी, आर्थिक विकास के स्तर वाले दो देश हैं। हमारी महत्वाकांक्षा का दायरा अलग है, इसलिए हमारी ताकत है। भारत की एक वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा है, राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से है। नेपाल की महत्वाकांक्षा अधिक स्थिर और समृद्ध देश होने की है।

एक करीबी पड़ोसी के रूप में, हमें भारत की अविश्वसनीय उपलब्धियों को देखकर खुशी हो रही है: चाहे वह बुनियादी ढांचे का निर्माण हो या औद्योगीकरण; चाहे वह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति हो, या सात दशकों के सफल लोकतांत्रिक व्यवहार के संदर्भ में हो।

आज जैसा कि हम कोविद 19 टीकों की उपलब्धता के लिए प्रतीक्षा करते हैं, भारत उन कुछ अग्रणी देशों में से एक है जिन्होंने लोगों को टीका़ लगाना प्रारंभ कर दिया है। इससे हमें बड़ी आशा जगी है। मैं इस अवसर पर भारत और उसकी नवीन कंपनियों को सफलता के लिए बधाई देता हूं। पड़ोसी होने के नाते, हमें विश्वास है कि हम भी इन टीकों का लाभ उठाएगें।

प्रिय मित्रो,

नेपाल उन कुछ देशों में शामिल था जो अपने पूरे इतिहास में स्वतंत्र रहे। इस तथ्य में आज के 30,0,000 नेपाली लोगों के राष्ट्रीय गौरव की प्रचुर भावना निहित है। इसलिए हम संप्रभु समानता, पारस्परिक सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों से अधिक प्रिय हैं।

हम स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं और बाहरी संबंधों का हमारा आचरण संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। सभी के साथ सौहार्द और किसी के साथ दुश्मनी नहीं हमारा आदर्श वाक्य है। उन्हीं सिद्धांतों से निर्देशित, हम पड़ोसियों और विश्व भर के सभी मित्र देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि तीन वर्ष पहले इसी शहर में नेपाल ने हमारे संबंधों में विश्वास की मजबूत इमारत बनाने की इच्छा जताई थी; एक ऐसा संबंध बनाने की इच्छा जताई जो हमारी पीढ़ी और भविष्य को समान रूप से गौरवान्वित करे। हम 21वीं सदी के नेपाल-भारत संबंध को देखना चाहते हैं, जो समानता, पारस्परिक सम्मान, न्याय और एक-दूसरे की चिंताओं और संवेदनाओं की समझ पर आगे की ओर देख रहा है और दृढ़ता से स्थापित है।

इसके लिए, हमें उन मुद्दों पर ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए जो हमें अतीत से विरासत में मिले हैं; उन्हें उचित रूप से संबोधित करें और भविष्य के लिए रचनात्मक रूप से कार्य करे। इसी उद्देश्य के साथ, हमने 2016 में एक प्रख्यात व्यक्ति समूह बनाया और उन्हें नेपाल-भारत संबंधों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने और बदले हुए संदर्भ में उन्नयन के उपायों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया। ईपीजी ने अपना काम किया है और हमारा काम उनकी रिपोर्ट प्राप्त करना और लागू करना है।

ईपीजी को सौंपे गए कार्यों में से एक 1950 की शांति और मैत्री संधि सहित पिछली संधियों और समझौते की समीक्षा के लिए आदानों की सिफारिश करने का काम था। हम वर्तमान वास्तविकता को बेहतर बनाने और अपनी मित्रता को अधिक प्रगाढ़ और विस्तारित करने के लिए संधि को संशोधित, समायोजित और अद्यतन करने पर सहमत हुए हैं। हमें इसे बाद की तुलना में जल्दी करने की आवश्यकता है।

अंत में हमारा दृढ़ विश्वास अटूट है कि नेपाल-भारत मैत्री एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी है। हमारा संबंध गहरा और संलिप्तता व्यापक है। फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ संबंधों को बदलती गतिशीलता में एक-दूसरे को समझने के लिए निरंतर पोषण, रचनात्मक सोच, तत्परता और तत्परता की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है कि हमारे पास वह क्षमता है।

धन्यवाद!